

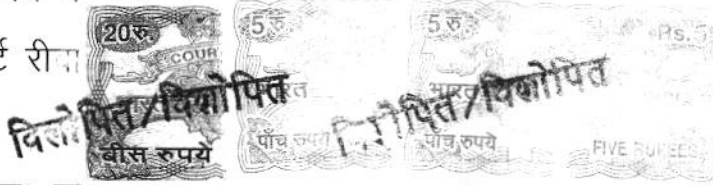
84

191

न्यायालय श्री मान सदस्य मन्देश

सार्किट कोर्ट रीवा

R.5384-4/16



त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय तनय स्व० राजमन्देश मन्देश उम्र ५० वर्ष १९११ कृ०  
निवासी ग्राम डकवार तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० ---निगरानी कर्ता  
बनाम

1-रामकृपाल कुशवाहा तनय श्री सुखलाल कुशवाहा उम्र 65 वर्ष पेशा खेती  
निवासी ग्राम कुटुलिया तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०

2- शासन म०प्र०

--- गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश  
न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार  
महोदय, तह० हुजूर जिला रीवा के  
प्रकरण क्र० 5/अ12/13-14 निर्णय  
दिनांक 20-04-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

अविष्टक आभिमोक्षक  
श्री रामजी जागल सिंह तिया  
द्वारा पेशा / 01-09-16  
1-9-16  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म० प्र० न्यायविपर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

आराजी नं० 87 निगरानी कर्ता के पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें निगरानी कर्ता के पिता व चाचा लोग जमीन के भूमि स्वामी मालिक थे जिसमें निगरानी कर्ता के चाचा श्यामलाल अपना 1/3 हिस्सा विवादित भूमि के अलावा जमीन गैर निगरानी कर्ता क्र० 1 को बिक्री कर दिया था तब गैर निगरानी कर्ता क्र० 1 द्वारा उस जमीन पर कब्जा ना कर आराजी नं. 87 के 1/3 भाग पर कब्जा किया एवं सिविल न्यायालय में गलत चौहद्दी बता कर आराजी नं० 87 के 1/2 भाग की डिक्री एक पक्षीय प्राप्त किया जिसमें निगरानी कर्ता उसमें पक्षकार नहीं था । एक पक्षीय डिक्री के बाद चोरी चोरी तहसील से नामान्तरण कराया जिसका विरोध निगरानी कर्ता द्वारा किया गया एवं तहसीलदार महोदय, के आदेश पारित करने के बाद निगरानी कर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जो आज भी लम्बित है। वहां से निगरानी कर्ता को स्थगन आदेश भी प्राप्त



त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5384-II/2016

जिला-रीवा

त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय/रामकृपाल कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामउजागर सिंह तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 5/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p> <p style="text-align: right;">  </p>	